मुनाफे की मिठास हुई कम...

बिजनेस स्टैंडर्ड 1-1, 10-10-14

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 9 अक्टूबर

भले ही केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने उत्तर प्रदेश की निजी चीनी मिलों के लिए निर्यात सब्सिडी और अतिरिक्त ब्याज-मुक्त ऋण का संकेत दिया है, लेकिन पेराई सत्र 2013-14 के लिए चीनी मिलों पर गन्ना बकाया अभी भी 3000 करोड़ रुपये से अधिक बना हुआ है।

राज्य सरकार और निजी चीनी मिलों के बीच गतिरोध बना हुआ है और इसे लेकर आगामी पेराई सत्र पर भी अनिश्चितता दिख रही है। 5 सितंबर 2014 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हालांकि याचिका पर सुनवाई करते हुए मिलों को बकाया निपटाने के लिए 31 अक्टूबर 2014 तक अपना चीनी स्टॉक बेचने का निर्देश दिया था।

उस समय निजी मिलों के पास लगभग 27.5 लाख टन चीनी थी जो वर्ष 2013-14 के दौरान उत्तर प्रदेश में 119 मिलों द्वारा 64.5 लाख टन के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 42 फीसदी है। इन चीनी मिलों में निजी, सहकारी (23 मिलें) और एक सरकारी निगम इकाई शामिल हैं। मिलों पर गन्ना बकाया लगभग 4600 करोड़ रुपये का था जो लगभग 5 सप्ताह में घट कर अब 3000 करोड़ रुपये रह गया है।

हालांकि सहकारी और राज्य निगम मिलें बकाया का भुगतान पहले ही कर चुकी हैं, लेकिन निजी मिलें बकाया निपटान के मामले में पीछे हैं। राज्य में निजी मिलों की तादाद 95 है और अधिक क्षमता वाली इकाइयों और मजबूत क्षमता की वजह से चीनी उत्पादन में इनकी बड़ी भागीदारी है। हालांकि कुछ प्रमुख निजी मिलों ने पूरे बकाया का भुगतान कर दिया है।

उत्तर प्रदेश में ऐसी लगभग 66 निजी मिलों की पहचान की गई है जिनमें आगामी सत्र में परिचालन बंद होने की आशंका है। इन मिलों की मांग है कि सरकार सबसे पहले गन्ना कीमत निर्धारण के लिए वैज्ञानिक फॉर्मूले को अपनाए।

चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश में ऊंची गन्ना कीमत को बनाए हुए है और कम रिकवरी प्रतिशतता कई सत्रों के दौरान बड़े बकाया की मुख्य वजह रही है। चीनी मिलें यह भी चाहती हैं कि राज्य सरकार अगले पेराई सत्र के लिए गन्ने की कीमत निर्धारित करने के लिए 'सहभागिता' और 'परामर्श' की व्यवस्था को अपनाए।

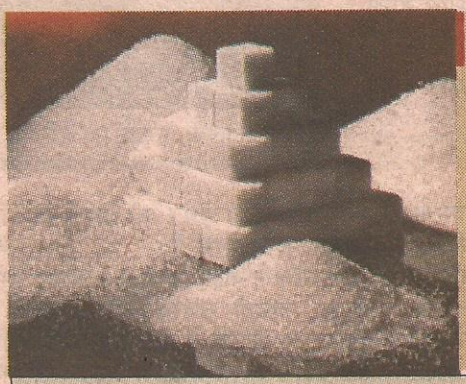

मुश्किलों का अंबार

- चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का अब भी 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया
- उत्तर प्रदेश सरकार और चीनी मिलों के बीच गतिरोध है कायम, पेराई सत्र पर अनिश्चितता
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चीनी बेच कर 31 अक्टूबर तक बकाया चुकाने का दिया निर्देश
- केंद्र से ब्याज मुक्त कर्ज, सब्सिडी की आस

...और चीनी मिलों का निकला दम

चीनी की कीमतों में गिरावट का रुख के चलते चलते देश की एक नामी गिरामी चीनी मिल को बैंक का कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया है तो वहीं लगातार चार वर्षों से चली आ रही बढ़ी आपूर्ति दूसरी कई मिलों के लिए यही राह तैयार कर सकती है। देश की सबसे बड़ी चीनी मिलों में से एक मवाना शुगर्स लिमिटेड ने बताया है कि वह कर्जदाताओं के एक समूह का 2.5 अरब रुपये का बकाया कर्ज चुकाने में नाकाम रही है।

जून में समाप्त हुई तिमाही में 24.52 करोड़ रुपये का नुकसान झेलनी वाली कंपनी के एक निदेशक राजेंद्र खन्ना ने बताया, 'हमें चीनी पर प्रति किलो 5 से 6 रुपये का नुकसान हो रहा है। गन्ने और चीनी की मौजूदा कीमतों को देखते हुए मिलों के लिए परिचालन मुश्किल हो गया है। गन्ने और चीनी की कीमतों में अंतर के चलते हम एक टर्म लोन नहीं चुका पाए।' दुनिया भर में जबरदस्त आपूर्ति के चलते चीनी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार टूट रही हैं, जिसकी वजह से चीनी मिलों का गणित गड़बड़ा रहा है। भारत में तो इनके सामने और भी ज्यादा मुश्किलें नजर आ रही हैं क्योंकि प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने चीनी मिलों के लिए गन्ने की कीमत 280 रुपये प्रति क्विंटल तय की, जबकि केंद्र सरकार ने इसके लिए 210 रुपये प्रति क्विंटल का भाव निर्धारित किया है। राज्य सरकार ने 'उचित एवं लाभकारी मूल्य' के आधार पर मिलों के लिए यह बढ़ी हुई कीमत तय की।

अभी वर्ष 2014-15 का पेराई सत्र चालू होना बाकी है लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने गन्ने की कीमत निर्धारित नहीं की है, मगर अधिकांश मिलों ने तब तक पेराई करने से इनकार करने का फैसला किया है, जब तक राज्य गन्ने की कीमतों को चीनी के भाव के अनुरूप नहीं लाता। पिछले एक साल के दौरान चीनी की कीमतों में तकरीबन 13 फीसदी की गिरावट आई। वहीं पिछले वर्ष में राज्य समर्थित गन्ना कीमतें 65 फीसदी तक चढ़ी हैं, जबकि चीनी की कीमतों में केवल 1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

रॉयटर्स

पिछले साल चीनी मिलों ने समान समस्याओं की वजह से पेराई को लेकर अनिच्छा जताई थी। इस मामले को राज्य सरकार के साथ सुलझाया गया और उद्योग को रियायतें देने और भविष्य में गन्ने की कीमत तय करने के लिए एक तार्किक एवं स्थायी फॉर्मूला बनाने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाए जाने क घोषणा की गई थी। इस समिति द्वारा अपनी रिपो सौंपना अभी बाकी है। चीनी कंपनियां दावा कर रह हैं कि सरकार उनसे किए गए अपने वादे को पूरा कर में विफल रही है।